

दक्षिणी क्षेत्र के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका - कितना संतुलित*

आर. गांधी

देवियो और सज्जनो, नमस्कार!

2. आर्थिक विकास में वित्तीय क्षेत्र के महत्व और उसकी अग्रणी भूमिका ने अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं और निष्पादकों का ध्यान आकर्षित किया है। गोल्डस्मिथ (1969:400) के अनुसार, 'चलनिधि संसाधनों को जुटाने से आर्थिक विकास की गति बढ़ती है और आर्थिक निष्पादन उस स्तर तक बेहतर हो जाता है जिसके अंतर्गत निधियों का रुख उसके अधिकतम उपयोग की ओर हो जाता है, अर्थात् आर्थिक प्रणाली में निधि का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां से समाज को उसका सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके।'

3. श्रुपिटर के लेखन-कार्यों में वित्तीय संस्थाओं के विश्लेषण में बैंकिंग को आर्थिक विकास की पहली और अनिवार्य जरूरत माना गया है। विकास की समग्र प्रक्रिया में श्रुपिटर (1933 और 1939) ने बैंकिंग प्रणाली को दो प्रमुख एजेंटों में से एक प्रमुख एजेंट माना है (दूसरा एजेंट उद्यमिता है) इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक ऋण और आर्थिक विकास के बीच समुत्थान-शक्ति का संबंध है।

4. इसीलिए वित्तीय प्रणाली को संसाधनों के कुशल आबंटन में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का काम सौंपा गया है। वस्तुतः बैंकिंग प्रणाली का विशेष स्थान बन गया है क्योंकि इसका मुख्य कार्य जन सामान्य की बचतों को संग्रहीत करना तथा उसका विभिन्न उत्पादक गतिविधियों के लिए कुशल आबंटन करना है और उद्यमियों के ऐसे वर्ग को सुविधा उपलब्ध कराना है जिन्हें किसी भी प्रकार की औपचारिक वित्तीय सेवा नहीं प्राप्त हो पाती है। भारत के संदर्भ में, आर्थिक गतिविधियों के लिए इस प्रकार से संसाधनों के आबंटन का कार्य मुख्यतया बैंकों द्वारा किया जाता है, किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी

इस कार्य को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। भारत में, सामाजिक बैंकिंग के संदर्भ में 1970 तथा 1980 के दशक में बैंकिंग प्रणाली को मार्गदर्शन/दिशानिर्देश जारी किए गए थे तथा 1990 के दशक में व्यापक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रारंभ किए जाने से आर्थिक कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण के अंतरालों को दूर करने में मदद मिली थी। इसके अतिरिक्त, हाल के दशक में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए वित्तीय समावेशन तथा संबंधित नीतिगत उपायों से बैंक इस दिशा में काफी दूरी तय कर सके हैं और उन्होंने बहुत छोटे और छोटे उद्यमों, गली-कूचे के विक्रेताओं, छोटे कारोबार करने वाले उद्यमियों आदि में कोई फर्क नहीं किया।

5. भारत एक विशाल देश है और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की स्थिति भिन्न-भिन्न है तथा उनकी विकास की गति भी अलग-अलग है। सार्वजनिक नीति में इसपर अवश्य ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इन नीतियों में ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जो क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास के स्तर एवं गति के लिए रणनीति के अनुकूल हों।

6. आज, मैं 'दक्षिणी क्षेत्र के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका' विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। चूंकि बैंक वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी हैं, इसलिए मेरी बात क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं उसकी भावी संभावनाओं के लिए बैंकों की भूमिका पर केंद्रित होगी। मैं आपसे निम्नानुसार बातें करना चाहूंगा:

(ए) मैं, दक्षिण क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करूंगा।

(बी) उसके बाद में विकास के लिकेज का विश्लेषण इन बिंदुओं के आधार पर करूंगा (i) जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में जमाराशियां (ii) जीएसडीपी की तुलना में बैंकों के ऋण (iii) ऋण/जमा अनुपात और (iv) क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के संसाधन के आबंटन में शहरी सहकारी बैंक (v) एनबीएफसी की भूमिका और (vi) वित्तीय समावेशन - क्षेत्र में सामान्य प्रवृत्ति

(सी) उसके बाद, मैं क्षेत्र में हो रही प्रगति में बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाओं तथा क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा और क्या किया जा सकता है, पर चर्चा करूंगा।

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 जुलाई, 2014 को हैदराबाद में फिक्की द्वारा आयोजित फिनसेक - 2014 के अवसर पर दिया गया भाषण। श्री एस. अरुणाचलरमणन द्वारा इस संबंध में दी गई सहायता के प्रति आभार।

आर्थिक विकास

7. 1980 दशक में सुधार से पूर्व के समय में दक्षिण क्षेत्र के राज्यों की विकास-दर सामान्यतया अखिल भारतीय विकास दर से कम थी। 1990 के दशक में, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र सुधार के बाद, इन राज्यों ने अखिल भारतीय विकास दर से बेहतर विकास-दर हासिल की। पिछले 10 वर्ष और उससे अधिक समय में विकास की दर अधिक ही रही है, क्योंकि वित्तीय समावेशन को बहुत अच्छी तरह से लागू किया गया (कृपया सारणी 1 देखें)।

प्रति व्यक्ति आय

8. आइये, आर्थिक समृद्धता के एक और संकेतक अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय के बारे में नज़र डालें। अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय पिछले तीन दशक में अधिक अच्छी रही है। सच यह है कि 1980 के दशक में इस क्षेत्र की औसत प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत से कम थी। 1990 के दशक में केरल और तमिलनाडु की औसत प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत से पार कर गई, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की औसत प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा कम थी। लेकिन, 200 के दशक में पूरे क्षेत्र का औसत, राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक था (सारणी 2)।

बैंकिंग संकेतक

कार्यालयों की संख्या

9. अब हम यह देखेंगे कि क्षेत्र की प्रगति में वित्तीय प्रणाली के रूप में कमर्शियल बैंकों ने क्या भूमिका अदा की है। कमर्शियल बैंक, जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तथा उत्पादक गतिविधियों में निवेश कर रहे हैं। तथा बैंकिंग के कार्यकलापों को विस्तार दे रहे हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपने

सारणी 1 : दक्षिणी क्षेत्र के आर्थिक विकास की दर

(प्रतिशत)

विवरण	सुधार से पूर्व अवधि 1980-81 से 1990-91	सुधार के बाद की अवधि		वित्तीय समावेशन मुहिम 2006-07 से 2013-14
		1991-92 से 2000-01	2001-02 से 2005-06	
आंध्र प्रदेश	5.0	5.4	6.8	8.0
कर्नाटक	5.2	6.9	6.2	6.8
केरल	2.4	5.0	7.6	7.8*
तमिलनाडु	5.7	11.6	6.3	8.6
अखिल भारत	5.6	5.7	6.8	7.4

* : आंकड़ा 2006-07 से 2012-13 की अवधि से संबंधित है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सारणी 2 : मौजूदा मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) पर आधारित दक्षिणी क्षेत्र की औसत प्रति व्यक्ति आय

(राशि ₹ में)

राज्य	सुधार से पूर्व अवधि	सुधार के बाद की अवधि			
	1980-81 से 1990-91	1991-92 से 2000-01	2001-02 से 2005-06	2006-07 से 2013-14*	
आंध्र प्रदेश	2557	10673	22760	58798	
कर्नाटक	2765	11497	23438	59053	
केरल	2586	12388	27777	61994	
तामिलनाडु	2857	13020	26433	73302	
अखिल भारत (निवल राष्ट्रीय आय)	3364	11616	22253	51519	

* : 2013-14 के आंकड़े छोड़कर क्योंकि केरल राज्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

कार्यालय स्थापित किए हैं। क्षेत्र (पुडुचेरि संघशासित क्षेत्र और लक्ष्य द्वीप को छोड़कर) कार्यालयों की संख्या मार्च 1999 के अंत में 17,613 थी जिसमें तेजी से विस्तार किया गया और वह मार्च 2013 में बढ़कर 29,135 (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) हो गई।

बैंकों की भूमिका

10. मैं, क्षेत्र के विकास में बैंकों की सहभागिता को रेखांकित करना चाहूंगा। बैंकों की भूमिका मापने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर इस प्रकार बनाये हैं : (ए) जीएसडीपी की तुलना में जमाराशियां, (बी) जीएसडीपी की तुलना में ऋण और (सी) ऋण/जमा अनुपात/बैंकों की भूमिकाओं को नीचे दी गई श्रेणियों के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है जिसे इसे प्रकार देखा गया है : (ए) वित्तीय क्षेत्र सुधार के

सारणी 3 : बैंक कार्यालयों की संख्या : दक्षिणी क्षेत्र

राज्य	सुधार पूर्व अवधि *	सुधार के बाद की अवधि			
	1980-81 से 1990-91	1991-92 से 2000-01	2001-02 से 2005-06	2006-07 से 2012-13	
आंध्र प्रदेश	3709	4863	5286	6754	
कर्नाटक	3187	4483	4850	5932	
केरल	2606	3055	3399	4205	
तामिलनाडु	3691	4548	5635	5481	
दक्षिणी क्षेत्र	13193	16949	19170	22372	
अखिल भारत	49823	63032	67065	82732	

स्रोत : दिए गए आंकड़े रिपोर्ट किए गए बैंक कार्यालयों की औसत संख्या है जिनका आकलन भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी पर आधारित है। विभिन्न अंक, भारतीय रिजर्व बैंक

* : दक्षिणी राज्यों के लिए सुधार पूर्व अवधि के आंकड़ों में 1988 और 1989 के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

सारणी 4 : निष्पादन के महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक : दक्षिणी क्षेत्र

(प्रतिशत)

वर्ष	विवरण	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	अखिल भारत
2013	जमा राशि - जीएसडीपी अनुपात	52.8	88.6	67.0	60.0	75.1
	ऋण - जीएसडीपी अनुपात	58.1	63.2	49.2	73.8	58.6
	ऋण - जमा अनुपात	109.9	71.4	73.3	123.0	78.1
2001	जमा राशि - जीएसडीपी अनुपात	37.6	51.3	62.3	43.2	47.5
	ऋण - जीएसडीपी अनुपात	23.8	30.4	26.8	39.2	27.8
	ऋण - जमा अनुपात	63.3	59.3	43.1	90.6	58.5
1991	जमा राशि - जीएसडीपी अनुपात	31.8	41.3	54.6	43.1	37.6
	ऋण - जीएसडीपी अनुपात	26.3	35.5	32.3	43.3	24.9
	ऋण - जमा अनुपात	82.6	85.8	59.1	100.5	66.2
1981	जमा राशि - जीएसडीपी अनुपात	28.0	37.1	39.8	36.8	32.3
	ऋण - जीएसडीपी अनुपात	21.1	28.5	28.5	35.0	22.0
	ऋण - जमा अनुपात	75.3	77.0	71.5	95.1	68.1

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

पहले, (बी) वित्तीय क्षेत्र सुधार अवधि के बाद और (सी) समावेशी विकास अवधि । 1991 से पूर्व 1981 आंध्र प्रदेश की संयुक्त जीएसडीपी की तुलना में जमाराशि मुश्किल से 28 प्रतिशत थी, जीएसडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 21.1 प्रतिशत था तथा जमाराशियों की तुलना में ऋण का अनुपात 75.3 प्रतिशत

था। यह स्थिति 2013 में क्रमशः बढ़कर 52.8 प्रतिशत, 58.1 प्रतिशत तथा 109.0 प्रतिशत स्तर तक बढ़ गई, जो इस बात को रेखांकित करता है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश में विकास के लिए बैंकिंग का विस्तार बहुत अधिक हुआ (सारणी 4)। वस्तुतः, बैंकों ने इससे भी गहन भूमिका अदा की, यहां तक कि शेष क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में।

शहरी सहकारी बैंक

11. आर्थिक गतिविधियों को निधियों के आबंटन के लिए वित्तीय प्रणाली में एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था का ढांचा है जिसे शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। मार्च 2014 के अंत में क्षेत्र में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 557 शहरी सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे। इन शहरी सहकारी बैंकों ने मिलकर मार्च 2014 के अंत तक कुल 48,461.42 करोड़ रुपए की जमाराशियां जुटाई और मार्च के अंत तक 32,146.15 करोड़ रुपए क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदान किए (सारणी 5)।

क्षेत्र में एनबीएफसी की भूमिका

12. दक्षिणी क्षेत्र में मार्च 2014 के अंत में, जमाराशि लेने वाली जमाराशि न लेनेवाली एवं प्रमुख निवेश कंपनियों की श्रेणी में 995

सारणी 5 : शहरी सहकारी बैंकों का लाभ - दक्षिणी क्षेत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	व्योरा	वर्ष	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	दक्षिणी क्षेत्र **	अखिल भारत
1.	श.स.बैं. की संख्या	2011	106	266	60	129	561	1,645
		2012	103	266	60	129	558	1,618
		2013	103	266	60	129	558	1,606
		2014	102	266	60	129	557	1,589
2.	अनुसूचित श.स.बैं. की संख्या	2011	3	1	शून्य	शून्य	4	53
		2012	2	1	शून्य	शून्य	3	52
		2013	2	1	शून्य	शून्य	3	51
		2014	2	1	शून्य	शून्य	3	51
3.	गैर-अनुसूचित श.स.बैं. की संख्या	2011	103	265	60	129	557	1,592
		2012	101	265	60	129	555	1,566
		2013	101	265	60	129	555	1,555
		2014	100	265	60	129	554	1,538
4.	जमा राशियां	2011	5,180.01	13,390.06	5,521.68	4,821.40	28,913.15	211,900.00
		2012	6,373.75	16,202.36	6,948.96	5,376.74	34,911.81	238,600.00
		2013	7,830.62	19,417.26	8,445.00	6,411.95	42,104.83	276,900.00
		2014	9,000.00	21,896.48	9,970.00	7,594.93	48,461.41	308,200.00*
5.	ऋण एवं अग्रिम	2011	3,865.79	9,402.08	3,849.72	3,781.36	20,898.95	136,500.00
		2012	4,614.97	11,475.00	4,720.00	4,394.96	25,204.93	157,800.00
		2013	5,436.02	12,936.54	5,934.00	5,047.42	29,353.98	181,000.00
		2014	5,709.00	15,034.00	6,188.00	5,215.15	32,146.15	197,700.00*

*आंकड़े अनंतिम हैं ** पांडुचेरी और लक्षद्वीप संघशासित को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 6 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या : दक्षिणी क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	वर्ष	श्रेणी 'ए' (जमा राशि लेनेवाली)	श्रेणी 'बी' (जमा राशि न लेनेवाली)	श्रेणी 'सी' प्रमुख निवेश	नये (श्रेणी बी मई 1998 से)	गै-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2011-12	2	231	शून्य	33	266
		2012-13	1	199	1	40	241
		2013-14	1	186	2	39	228
2.	कर्नाटक	2011-12	7	102	शून्य	34	143
		2012-13	7	100	3	32	142
		2013-14	7	102	3	32	144
3.	केरल	2011-12	13	115	शून्य	27	155
		2012-13	12	114	शून्य	29	155
		2013-14	12	113	शून्य	33	158
4.	तामिलनाडु	2011-12	37	421	शून्य	39	497
		2012-13	35	395	1	37	468
		2013-14	34	391	1	39	465
5.	दक्षिणी क्षेत्र	2011-12	59	869	शून्य	133	1,061
		2012-13	55	808	5	138	1,006
		2013-14	54	792	6	143	995
6.	अखिल भारत	2011-12	271	11,190	शून्य	924	12,385
		2012-13	254	10,982	12	977	12,225
		2013-14	241	10,810	15	963	12,029

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

गैर-बैंकिंग एवं प्रमुख निवेश कंपनियों भी; जबकि पूरे भारत में यह संख्या 12,029 थी। क्षेत्र के राज्यों में, जमाराशि लेने वाली वित्तीय कंपनियां तमिलनाडु राज्य में बहुत ही सक्रिय हैं (सारणी 6 और 7)।

13. आर्थिक गतिविधियों को निधि प्रदान करने के संबंध में, जमाराशि लेने व न लेने वाली कंपनियों द्वारा उधार दिया जाना सबसे अधिक तमिलनाडु में था, उसके बाद केरल में और संयुक्त आंध्र प्रदेश में। उन्होंने मार्च 2014 के अंत तक 1.90 लाख करोड़ रुपए उधार दिए (सारणी 8)।

दक्षिणी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन

14. भारत में, अभी भी, हमारी बड़ी आबादी का हिस्सा जो मुख्यतया कम अमीर तबका है, काफी हद तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित है। बैंकिंग सेवाओं को अब तक वित्तीय रूप से वंचित समाज तक ले जाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय समावेशन' कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार विशेष उपाय किए हैं जिसमें पूरे देश में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।

सारणी 7 : जमाराशि की स्थिति : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां : दक्षिणी क्षेत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	श्रेणी 'ए' (जमाराशि लेने वाली)
1.	आंध्र प्रदेश	2011-12	शून्य
		2012-13	शून्य
		2013-14	शून्य
2.	कर्नाटक	2011-12	7.02
		2012-13	8.49
		2013-14	10.07
3.	केरल	2011-12	79.39
		2012-13	80.19
		2013-14	185.41
4.	तामिलनाडु	2011-12	10,885.36
		2012-13	12,547.30
		2013-14	16,122.78
5.	अखिल भारत	2011-12	12,656.41
		2012-13	15,310.67
		2013-14	20,556.20

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

15. तदनुसार, रिजर्व बैंक ने वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जनवरी, 2006 में बैंकों को यह अनुमति दे दी कि वे व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) तथा व्यवसाय सहायक (बीएफ) की सेवाएं मध्यस्थ के रूप में लें। रिजर्व बैंक ने समय-समय पर ऐसे पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को बृहत बना दिया है जिनकी

सारणी 8 : ऋण और अग्रिम : गैर - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां : दक्षिणी क्षेत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	श्रेणी 'ए' (जमा राशि लेनेवाली)	गैर्बैंकिंग - जमाराशि न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडीएसआई)
1.	आंध्र प्रदेश	2011-12	174.73	11,135.92
		2012-13	236.03	15,175.10
		2013-14	297.17	13,374.24
2.	कर्नाटक	2011-12	30.36	5,584.35
		2012-13	36.27	6,924.41
		2013-14	20.46	8,777.11
3.	केरल	2011-12	527.81	40,715.84
		2012-13	758.96	50,288.16
		2013-14	978.41	43,445.94
4.	तमिलनाडु	2011-12	54,846.60	80,768.97
		2012-13	71,978.63	100,021.34
		2013-14	79,990.08	111,482.55
5.	अखिल भारत	2011-12	90,593.94	639,480.36
		2012-13	101,102.27	760,039.01
		2013-14	136,404.30	844,835.69

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सेवाओं का इस्तेमाल बीसी के रूप में किया जा सकता है। बीसी मॉडल के माध्यम से बैंक दरवाजे तक सेवाएं दे पा रहे हैं, खासतौर से आबादी इसे नजदीक स्थान पर नकद लेने-नकदी देने में, इस प्रभार से, अंतिम मील तक सेवाएं प्रदान करने की समस्या का समाधान कर रहे हैं।

16. हमने एक बनाए रखे जाने योग्य, सुनियोजित तथा संरचित वित्तीय समावेशन के प्रयास के रूप से सभी सरकारी और निजी क्षेत्र बैंकों को सूचित किया है कि वे लक्ष्यों को मार्च 2016 तक पूरा करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना कार्यान्वित करें। इसके अलावा, हमने बैंकों से कहा है कि वे अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना को अपने कारोबार की योजना से जोड़ें और वित्तीय समावेशन के मानदंड को अपने स्टाफ के कार्यनिष्पादन के मानदंड को अपने स्टाफ के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के पैरामीटर के रूप में शामिल रहें।

17. फलस्वरूप, बैंकों ने लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। मुझे खुशी है कि कमर्शियल बैंक 'वित्तीय समावेशन' कार्यसूची के अंतर्गत समस्त दक्षिणी क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। जहां 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को कवर कर लिया गया है, वहीं 2000 से कम आबादी वाले गांवों को पूरी तरह से कवर करने की कार्रवाई में अच्छी प्रगति हुई है।

18. क्रिसिल के वित्तीय समावेशन सूचकांक - इन्क्लूसिव्स के अनुसार, जिसमें शाखा के फैलाव के तीन पैरामीटर हैं - जमाराशियों और ऋण का विस्तार 100 के मान पर, 2012 में दक्षिणी क्षेत्र द्वारा प्राप्त किया गया वित्तीय समावेशन अखिल भारतीय स्तर 42.8 बिंदु की तुलना में सर्वाधिक 66.1 बिंदु था। यह इस बात का संकेत है कि पूरे देश तथा इस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है।

इस क्षेत्र के लिए और कितना - संतुलनकारी कार्य

19. अब हम यह चर्चा करेंगे कि बैंकिंग प्रणाली इस क्षेत्र के लिए और क्या कर सकती है। बैंकिंग प्रणाली से इस क्षेत्र को बहुत सी उम्मीदें हैं और बैंकिंग प्रणाली पर अनेक बाध्यताएं हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र की कुछ खास विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के प्रति बैंकिंग प्रणाली की एक मानक प्रतिक्रिया यह होती है कि वे उससे बचना चाहते हैं। मेरे विचार से, बैंकिंग प्रणाली को उनसे बचने के बजाय वे उन विशेषताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के निर्धारण का पालन करने के लिए इनके बीच एक अच्छा सा संतुलन बनाएं।

- पहली बात निश्चित रूप से यह है कि यह क्षेत्र बैंकों से अपने विकास में निरंतर सहायता की उम्मीद करता है ताकि विकास को बचपन से रखा जा सके। अर्थात्, यह क्षेत्र 100 प्रतिशत से अधिक सीडीआर बनाए रखना चाहता है। जहां बैंकिंग प्रणाली इस अपेक्षा को पूरा करने में भागीदार बनना चाहेगा, वहीं उसे शेष भारत के साथ भी संतुलन बना कर चलना होगा। प्रत्येक क्षेत्र अधिक से अधिक ऋण के प्रवाह तथा वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए स्पर्धा कर रहा है और बैंकिंग प्रणाली की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे पूरा करे।
- दूसरी बात यह है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक लहरों के प्रति संवेदनशील है और प्राकृतिक आपदाएं इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित करती हैं, खासतौर से कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। कृषि क्षेत्र को सतत रूप से ऋण उपलब्ध कराना एक चुनौती है। यह कार्य मुश्किल इसलिए है क्योंकि कृषि क्षेत्र में बीमा की योजनाएं असरदार नहीं हैं। इस क्षेत्र में एक खास, किंतु लोकप्रिय आदत है स्वर्ण ऋण लेना, जिसने कृषि संबंधी ऋणों को दबा रखा है। इस समस्त प्रक्रिया में किसानों को कृषि-बीमा का फायदा नहीं मिल पाता है। बैंकिंग प्रणाली को इस विवादास्पद समस्या का हल ढूंढना होगा और उनकी आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए किसानों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी। मैं

स्वर्ण ऋण से संबंधित एक अन्य प्रकार की समस्या पर चर्चा थोड़ी ही देर में आपसे करूंगा।

- तीसरी बात यह है कि अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र को भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की बढ़ती हुई उपलब्धता की जरूरत है। जैसाकि सभी जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए लगातार बैंक ऋण की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद इस क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण का प्रवाह बहुत कम है क्योंकि इसकी तुलना में इस क्षेत्र में ऐसी इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है और बैंकिंग क्षेत्र को चाहिए कि वे इस क्षेत्र की कार्य-क्षमता का फायदा उठाएं। इस संबंध बैंकिंग प्रणाली को सबसे बड़ी परेशानी जिसका सामना करना पड़ रहा है वह है बहुत से दस्तावेजों की जरूरत, एमएसएमई की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए पारंपरिक तरीका और कई बार बैंक अधिकारियों की मनोवृत्ति एवं संवेदनशीलता में भी अंतर पाया जाता है।
- चौथी बात यह है कि इस क्षेत्र की एक अन्य विशेषता यह है कि वहां पर बचत करने के अनौपचारिक और औपचारिक साधनों की पहले से ही भरमार है, किंतु बहुत ही जोखिमपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में ऐसी कंपनियों का पुराना इतिहास रहा है जो लोगों का पैसा लेकर गायब हो गईं, अनेक प्रकार की औपचारिक एवं अनौपचारिक चिट फंड, पाँजी योजनाएं, विद्युत चुंबकीय इकाइयां तथा अन्य प्रकार की आकर्षक योजनाएं रही हैं। इन योजनाओं ने इस क्षेत्र के भोले-भाले एवं सीधे लोगों का समय-समय पर ध्यान आकर्षित किया है और प्रलोभन देकर उनकी गाढ़ी कमाई हजम कर ली है। इस प्रकार के सतत प्रकरण से यह स्पष्ट है कि वहां बैंकिंग सहित औपचारिक वित्तीय प्रणाली बचत, निवेश और जोखिम उठाने की जरूरतों तथा लोगों की धन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में सफल नहीं है। इस बात की सख्त आवश्यकता है कि वहां की बचत को उपयुक्त तरीके से संग्रहीत किया जाए और उस क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जो साधारण एवं सामान्य से अधिक जोखिम उठा सकते हैं इसलिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली उन्हें अच्छी तरह से विनियमित जोखिमपूर्ण वित्तीय उत्पाद का प्रस्ताव सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली को नये एवं बचत तथा वित्त के बड़े आसान से उत्पाद लाने की जरूरत है। इस प्रकार वे उस क्षेत्र

के लोगों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं से अपने कारोबार के अवसरों को संतुलित कर सकते हैं।

- पांचवीं बात, इस क्षेत्र की एक अन्य उल्लेखनीय एवं सुखद विशेषता है। उसका संबंध स्वयं सहायता समूह से है, विशेष रूप से महिलाओं से जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं। वस्तुतः दक्षिणी क्षेत्र इस बारे में हर तरह से आगे है। इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की तत्परता, उत्साह और समर्पण तथा अनुशासन उनकी सफलता का आधार है। उनकी सफलता को देखते हुए कतिपय अवांछित परंपराएं एवं कुछेक बेकार की प्रतिक्रियाओं से उनके कार्यों में धीमापन आ गया है, यहां तक कि उस क्षेत्र में ऋण-प्रवाह बंद सा हो गया है। इसके अलावा, उनमें से कई स्वयं सहायता समूहों को ऋण और वित्त संबंधी कार्यों के संचालन में परिपक्व होने से पहले ही ऋण कार्यों का अनुभव था। फलस्वरूप, ऋण-अनुशासन जो कई वर्षों तक कष्ट उठाने के बाद अत्यधिक परिश्रम से बनाया गया था, वह भंग हो गया। उस भावना को बहाल करना तथा ऋण सुविधा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना बैंकिंग प्रणाली के लिए एक अन्य संतुलनकारी कार्य है।

निष्कर्ष

20. संक्षेप में, अभी हमने देखा कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ने सुधार से पहले की तुलना में सुधार के बाद और वित्तीय समावेशन अवधि में किस प्रकार से बदलाव देखा है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ने न केवल बेहतर विकास किया है बल्कि कई मामलों में अखिल-भारतीय संख्या से अधिक हासिल किया है। हमने यह भी देखा बैंकिंग प्रणाली ने इस क्षेत्र में पिछले तीन दशकों से किस प्रकार से जुटाए गए संसाधनों का आबंटन किया है, क्षेत्र का सतत एवं स्थायी आर्थिक विकास किया है। हमने यह भी देखा कि शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाकर और सेवाएं देकर तथा ऋण के आबंटन में सहायता प्रदान करके अपनी भूमिका अदा की है। अंतिम बात, हमने इस क्षेत्र की कुछ खास विशेषताओं पर चर्चा की और इसपर भी उनका बैंकों के परिचालनों क्या प्रभाव पड़ा तथा बैंकों को इन विशेषताओं के साथ काम करते समय किस प्रकार से नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।

21. ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद !